RAJYA SABHA

Wednesday, the 14*th March*, 2007/23 *Phalguna*, 1928 (*Saka*)

The House met at eleven of the clock,

[MR. CHAIRMAN in the Chair.]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्य लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं और आते नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज शुरुआत इस ढंग से करें कि सारे के सारे क्वेश्चन लिए जा सकें। सारे तो नहीं लिए जाएंगे लेकिन मैं आज दस की सीमा रखता हूं। क्वेश्चन-221।

Funds under ARWSP for Assam

*221. SHRI KALRAJ MISHRA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Assam Government has sought allocation of funds under the Centrally sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) for the State;

(b) if so, the details of the project proposal made by that State under ARWSP, and the estimated cost thereof; and

(c) the Central Government's response thereto, indicating the allocations made so far under the programme?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No, Sir. Allocations under the Centrally sponsored programme

Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) is made on the basis of certain guidelines approved by the Central Government and not on the basis of request or project proposals received from State Governments.

(c) Based on the Inter State allocation criteria, during Tenth Plan period (2002-03 to 2006-07), a total amount of Rs. 764.90 crores has been allocated by the Central Government for drinking water supply programmes in Assam.

श्री कलराज मिश्र: मान्यवर, इस प्रश्न के दो जवाब मिले हैं। एक तो अभी-अभी संशोधित करके भेजा गया है। पहले में यह था कि यह राज्य का विषय है इसलिए यहां का कोई अर्थ नहीं होता। अभी उन्होंने जवाब संशोधित करके भेजा है। तो उस पर मेरा प्रश्न है कि क्या कारण है कि वर्ष 2006 में असम को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए आबंटित 10299 लाख रुपए में से दिनांक 23-2-07 तक मात्र 2876.21 लाख रुपए ही खर्च हो पाए हैं। प्रस्तावित बसावट में जो 2428 में से 33 नॉन-कवर्ड हैं, 1404 आंशिक कवर्ड हो पाए हैं तथा 991 अभी भी छूट रहे हैं। इस संबंध में यद्यपि आप जवाब यही देंगे कि यह तो राज्य सरकार का विषय है, वह अपना करेगी, लेकिन इस सम्बन्ध में चूंकि यह भारत निर्माण के अन्तर्गत लिया गया है और एक प्रमुख घटक है और इस प्रमुख घटक को राज्यों में समुचित रूप से कार्यान्वित होना चाहिए, तो इसकी समीक्षा करने के लिए केन्द्र ने क्या व्यवस्था की है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, कानून में पानी स्टेट का विषय जरूर है। लेकिन भारत सरकार तत्पर है कि शुद्ध पीने का पानी लोगों का उपलब्ध हो जाए। माननीय सदस्य ने जो असम की स्थिति का नॉन-कवर्ड और पार्शली कवर्ड का जिक्र किया है। नॉन कवर्ड का मतलब, जहां कम से कम प्रति व्यक्ति दस लीटर पीने का पानी मिल जाए और जो पार्शली कवर्ड है जहां कम से कम 40 लीटर से कम है। यदि 40 लीटर से अधिक शुद्ध पीने का पानी है तो वह फुली कवर्ड है। महोदय, भारत निर्माण का लक्ष्य है कि 2009 तक देश की प्रत्येक आबादी में हम शुद्ध पानी का प्रबंध करा दें। हमारा जो टार्गेट है तथा उस मुताबिक जो एक्शन प्लान बना है हम राज्यों को पैसे देते हैं। यह ए॰आर॰डब्ल्यु॰एस॰पी॰ की स्कीम है, जो माननीय सदस्य का प्रश्न था। उसमें हम असम सरकार को पैसे दे रहे हैं और 2009 तक हम लक्ष्य हासिल कर लेंगे कि 40 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध पानी का प्रबंध हो जाए।

श्री कलराज मिश्र: क्या इसकी समीक्षा की है कि जो इतना कम खर्चा हुआ है और उसके अनुसार जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका कारण क्या रहा है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हम माहवारी समीक्षा करते हैं। हमको नॉर्थ ईस्ट में कठिनाई असम के साथ है कि हम 50 फीसदी राशि देते हैं और राज्य सरकार को अपना हिस्सा 50 फीसदी देना पड़ता है। लेकिन वह अपने आर्थिक संकट के चलते अपना 50 फीसदी हिस्सा नहीं जमा कर

पाते इसलिए फिर भी हम साल के अंत में यह कह कर कि अगले साल उपाय कर लेंगे, हम उनको दे देते हैं। महोदय, इस साल भी वहीं किया है।

श्री कलराज मिश्र: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि भारत निर्माण के जो आपके 6 प्रमुख घटक हैं, उनमें से एक प्रमुख घटक जल आपूर्ति है और इस प्रमुख घटक के, जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है, उसके अन्तर्गत जो रिपोर्ट है, जो बसावट के बारे में कहा गया है और जो 2006 तक किया है। उसमें जो विभिन्न प्रदेश हैं, विशेषकर पूर्वांचल भारत के अरूणाचल प्रदेश में 158बसावटें हैं, जो उसके अंतर्गत नहीं ली गई हैं,असम में 238 बसावटें हैं, जो इसके अंतर्गत नहीं ली गई हैं, जम्मू-कश्मीर में 660 हैं, महाराष्ट्र में 327 हैं, राजस्थान में 2300 हैं, पंजाब में 803 हैं, उत्तराखंड में 30 हैं, दादरा और नगर हवेली में 19 हैं, इतनी बसावटें अभी इसके अंतर्गत नहीं ली गई हैं और जो ली गई हैं, वे कब तक पूरी होंगी, उनके बारे मे पता नहीं हैं और जो नहीं ली गई हैं, उनके बारे में क्या आगे की योजना है? अगर ये आंकड़े सच हैं, चूंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, जो राज्यवार NCPC हैबिटेशन है, फिर silt belt भी हो जाता है, मान लिया कि पानी की कमी हो गयी, नई बसावट हो गयी, तो silt belt भी होती है, तीनों ही बातों के लिए हमारा लक्ष्य है कि हम उसको पूरा कर लेंगे। इसमें वर्षवार एक्शन प्लान राज्यों से हमने तैयार करा दिया है और हम महीने में एक बार मॉनिटरिंग करके, उनको जो राशि दे रहे हैं और संयोग से महोदय, इस बार पीने के पानी के बजट में बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए माननीय सदस्य की इस आशंका को हम हटा देना चाहते हैं कि 2009 तक कोई कमी नही रह जायेगी, हम पीने के लिए शुद्ध पानी का प्रबंध करवा देंगे।

श्री सभापति: सबको शुद्ध पानी पिला देंगे, ध्यान रखिएगा।

श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा: सभापति महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि जो नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित शेयर देने में कठिनाई होती है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजिशन असम और नार्थ-ईस्ट की इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट का है जिससे कि जो 60 परसेंट स्टेट् गवर्नमेंट्स का शेयर है, इसको कम करके नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कोई दूसरी स्कीम बनाई है या नहीं बनाई है? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जी, महोदय। नार्थ-ईस्ट के लिए जिन योजनाओं में 50 फीसदी राज्य सरकार और 50 फीसदी केन्द्र सरकार को देना होता है, इसके अलावा अन्य योजनाएं भी हैं। जिनमें

75 फीसदी केन्द्र सरकार और 25 फीसदी राज्य सरकार देती है। नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों की बराबर मांग रही है। कि जहां शेयर 75-25 का है, वहां 90-10 कर दिया जाए और जहां शेयर 50-50 का है, वहां 75-25 कर दिया जाए। हमने अपनी सहमति इसके बारे में दे दी है। अब योजना आयोग में विचार-विमर्श चल रहा है। मुझे खुशी होगी कि ग्यारहवीं योजना के शुरुआत में इस पर निर्णय हो जाए।

श्री सिलवियस कॉडपन: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि भारत और असम की सीमा के अंचल में बसे हुए गांव के लोगों को पीने का पानी बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने दफ्तर से असम सरकार के साथ सम्पर्क करके सरकार को बोलें कि सीमा के अंचल में बसे हुए गांव के लोगों की पीने के पानी की जो समस्या है, क्या उसको हल करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, यह ठीक बात है। बार्डर पर जो लोग बसे हुए हैं, उनकी तकलीफें दूर हो जाएं, इसलिए बार्डर एरिया डवलेपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाने पर हम खासध्यान रखेंगे और राज्य सरकार को कहेंगे कि बार्डर के एरिया पर बसे हुए लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे कि उनको पीने का शुद्ध पानी मिल सके।

SHRI P.R. RAJAN: Sir, will the hon. Minister be pleased to say whether there is any proposal; before the Government to replace the ARWSP by community contribution scheme, *Swajal Dhara*, from the Eleventh Plan onwards? The Standing Committee on Rural Development has expressed its serious concern over this issue. What is the decision of the Government?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, ए॰आर॰डब्ल्यू॰एस॰पी॰ स्कीम जो है, उसके तीन हिस्से हैं। 20 फीसदी स्वजलधारा, 20 फीसदी सबमिशन प्रोग्राम, जिसमें पानी की क्वालिटी जो पीने का अशुद्ध पानी है, उसके लिए है और बाकी 60 फीसदी जनरल एमसीपीसी के कवरेज के लिए है, अब उसमें 60, 20, 20 का रेश्यों बना हुआ है। महोदय, अब जो स्वजलधारा है, इसमें 10 फीसदी जनता के द्वारा दिया जाता है, जिनको पानी की जरूरत है और 90 फीसदी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, यह योजना चल रही है, लेकिन बहुत सफलता की ओर यह योजना नहीं बढ़ रही है, इसलिए इस पर हम पुनर्विचार कर रहे हैं। वैसे यह अच्छी योजना है जिसमें 10 कदम जनता चले और 90 कदम भारत सरकार चलें, यह समस्या के समाधान के लिए है। बाकी राज्य का उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसलिए हम उस पर पुनिर्वचार कर रहे हैं।